दैनिक भारत कि
तामीर
संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-१ ला | अंक-२७२ वा | शुक्रवार २ मे २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

बीड जिले के विकास को सरकार की प्राथमिकता-इंद्रनील नाइक

गौरवशाली समारोह में महाराष्ट्र दिवस का भव्य आयोजन

बीड, १ मई (प्रतिनिधि):

बीड जिले के सर्वांगीण विकास को राज्य सरकार ने प्राथमिकता दी है। यहां की मूलभूत सुविधाओं को सशक्त बनाकर बीड को एक विकसित जिले के रूप में पहचान दिलाई जाएगी और इस दिशा में नागरिकों को भी सहयोग देना चाहिए, ऐसा प्रतिपादन राज्य के उद्योग व सार्वजनिक निर्माण राज्यमंत्री इंद्रनील नाइक ने महाराष्ट्र दिवस के मुख्य शासकीय ध्वजारोहण कार्यक्रम में किया।

यह समारोह बीड के पुलिस मुख्यालय के कवायत मैदान में आयोजित हुआ, जिसमें ध्वजारोहण मंत्री श्री नाइक के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिलाधिकारी विवेक जॉन्सन, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित्य जीवणे, तथा पुलिस अधीक्षक नवनीत कवत प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

श्री नाइक ने अपने भाषण की शुरुआत में संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में शहीद हुए १०५ हुतात्माओं और हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उद्योग-व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए निवेश-अनुकूल वातावरण तैयार किया है, जिससे कला, खेल, संस्कृति, साहित्य और उद्योग के क्षेत्र में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य बन गया है। इस दिशा में किए गए कार्यों के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार का आभार व्यक्त

किया।

राज्यमंत्री ने बताया कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा बीड का संपर्क मंत्री पद स्वीकारने के बाद जिले में विकास की दिशा में गति प्राप्त हुई है। जिला मुख्यालय में बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ एक नया हवाई अड्डा निर्माण कार्य की घोषणा की गई है, जिस पर तेजी से कार्य चल रहा है।

उन्होंने बताया कि रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए टाटा टेक्नॉलॉजी की सहायता से एक अत्याधुनिक इन्क्यूबेशन सेंटर बीड में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत १९१ करोड़ रुपये है, जिसमें से १६३ करोड़ रुपये टाटा टेक्नॉलॉजी निवेश करेगी और शेष भाग उद्योग विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

हाल ही में आयोजित बीड निवेश परिषद में कुल ९३० करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन (चेण) हस्ताक्षरित हुए हैं, जो जिले के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

बीड जिले को 'आद्यकवी मुकुंदराज' की धरती बताते हुए उन्होंने मराठी भाषा को हाल ही में प्राप्त अभिजात भाषा के दर्जे पर प्रसन्नता जताई और बताया कि अंबाजोगाई को पुस्तकाचे गाव घोषित किया गया है। इससे साहित्य, रंगमंच और सिनेमा के क्षेत्र में जिले की पहचान और मजबूत होगी।

उन्होंने बताया कि 'लाडकी बहन योजना' के अंतर्गत महिलाओं को बस यात्रा में रियायत दी जा रही है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा में छूट और महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के तहत बिना आय सीमा के १२ करोड़ नागरिकों को ५ लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है।

किसानों के लिए फसल बीमा, बिजली बिल माफी और सौर ऊर्जा आधारित पंपों जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों से इन योजनाओं का लाभ लेने की अपील की गई।

ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद पुलिस, होमगार्ड और अग्निशमन दल के जवानों द्वारा शानदार परेड का आयोजन हुआ। इसके उपरांत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और जिला खेल पुरस्कार विजेताओं को मंत्री महोदय के हाथों सम्मानित किया गया।

जिलाधिकारी कार्यालय में महाराष्ट्र दिवस पर ध्वजारोहण

महाराष्ट्र राज्य की ६६वीं वर्षगांठ के अवसर पर बीड जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में जिलाधिकारी विवेक जॉन्सन के हाथों ध्वजारोहण संपन्न हुआ। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी हरीश धार्मिक, निवासी उपजिलाधिकारी शिवकुमार स्वामी, उपविभागीय अधिकारी कविता जाधव, उपजिलाधिकारी शैलेश सूर्यवंशी समेत कई अधिकारी, कर्मचारी और नागरिक उपस्थित रहे। ध्वजारोहण के बाद जिलाधिकारी ने स्वतंत्रता सेनानियों और आम नागरिकों से भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दीं। मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत परिसर में भी ध्वजारोहण समारोह

महाराष्ट्र दिवस के उपलक्ष्य में बीड की मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत परिसर में भी ध्वजारोहण का आयोजन किया गया। यह ध्वजारोहण अपर जिलाधिकारी हरीश धार्मिक के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपविभागीय अधिकारी कविता जाधव, तहसीलदार चंद्रकांत शेलके, सभी नायब तहसीलदार एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाइक ने किया मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष का उद्घाटन

बीड, १ मई (प्रतिनिधि):

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देशानुसार बीड के जिलाधिकारी कार्यालय में स्थापित मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष का उद्घाटन आज उद्योग व सार्वजनिक निर्माण राज्यमंत्री इंद्रनील नाइक के हाथों संपन्न हुआ।

इस अवसर पर जिलाधिकारी विवेक जॉन्सन, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित्य जीवणे, पुलिस अधीक्षक नवनीत कवत, तथा सहायता कक्ष के प्रमुख चैतन्य कागदे प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

उद्घाटन के पश्चात श्री नाइक ने सहायता कक्ष का निरीक्षण किया तथा यहां की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। उन्होंने बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया।

यह सहायता कक्ष जिलाधिकारी कार्यालय की भूतल मंजिल पर स्थापित किया गया है। इस कक्ष में ऐसे जरूरतमंद नागरिक, जिन्हें चिकित्सकीय उपचार हेतु आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, वे आवेदन कर सकेंगे। कक्ष में न केवल आवेदन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, बल्कि संबंधित अस्पतालों से समन्वय और सहायता राशि भी यहीं से प्रदान की जाएगी।

पहले इस तरह की सहायता के लिए मुंबई तक आवेदन भेजना पड़ता था, लेकिन अब यह सुविधा सीधे जिला मुख्यालय पर उपलब्ध होने से जरूरतमंद मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।

सेल्फ फाइनेंस स्कूलों की मंज़ूरी की ऑनलाइन प्रक्रिया अत्यंत जटिल: 'फेम' के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने एजुकेशन कमिश्नर से की मुलाकात

मुंबई (संवाददाता): एक ओर जहाँ राज्य सरकार साक्षरता दर बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलें कर रही है, वहीं दूसरी ओर सीमित संसाधनों में छात्रों को शिक्षा से सुसज्जित करने का प्रयास कर रहे संस्थानों को अनावश्यक दस्तावेज़ी उलझनों में फँसाया जा रहा है।

इसी गंभीर मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल फेडरेशन (फेम) के राज्य समन्वयक शब्बीर शाकिर ने पुणे स्थित राज्य शिक्षा आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह से मुलाकात की।

इस अवसर पर शब्बीर शाकिर ने शिक्षा आयुक्त से विभिन्न शैक्षणिक

समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की, विशेषकर सेल्फ फाइनेंस स्कूलों की मंजूरी हेतु आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान आने वाली तकनीकी अड़चनों को लेकर।

उन्होंने बताया कि स्कूलों की मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल हो गई है। अधिकांश स्कूल स्टाफ को तकनीकी जानकारी न होने के कारण कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, जिन्हें सुधारना बेहद कठिन हो जाता है।

शब्बीर शाकिर के अनुसार, कई सेल्फ फाइनेंस स्कूलों ने पहले ऑफलाइन आवेदन किया था, फिर भी उन्हें अब दोबारा ऑनलाइन अनुमति लेनी पड़ रही है, और इस प्रक्रिया में अनेक तकनीकी समस्याएँ सामने आ रही हैं। शिकायतों को गंभीरता से सुनने के बाद शिक्षा आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को तलब कर तुरंत सकारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री मोदी के निर्णय का भाजपा करेगी राज्यव्यापी अभिनंदन प्रस्ताव-चंद्रशेखर बावनकुले

जातिगत जनगणना को बताया ऐतिहासिक कदम, ग्रामपंचायत से लेकर बूथ स्तर तक होंगे प्रस्ताव

मुंबई, जमीर काजी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जातिगत जनगणना कराने के निर्णय को क्रांतिकारी और ऐतिहासिक बताते हुए महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने राज्यभर में उनके अभिनंदन के प्रस्ताव पारित करने की घोषणा की है। यह जानकारी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर दी।

बावनकुले ने कहा कि भाजपा द्वारा यह प्रस्ताव एक लाख १८६ बूथ, १,२८० मंडल समितियां और २७,००० ग्रामपंचायतों में पारित किया जाएगा। उन्होंने कहा, जातिगत जनगणना देश में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास का नया अध्याय शुरू करेगी। यह लोकतंत्र को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को और मजबूत बनाएगा।

बावनकुले ने आगे सवाल उठाते हुए कहा, अब तक जातिगत जनगणना की मांग को लेकर आवाज उठाने वाले शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार अब चुप क्यों हैं? क्या वे मोदी सरकार के इस निर्णय का स्वागत करेंगे या फिर वही पुराना घृणास्पद राजनीतिक रवैया अपनाएंगे?

भाजपा का यह प्रस्ताव अभियान राज्यभर में संगठनात्मक स्तर पर चलाया जाएगा, जिसमें बूथ, मंडल और ग्राम पंचायत समितियों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्णय की सराहना की जाएगी।

औरंगाबाद के अब्दुल अन्सार को पीएचडी पदवी प्रदान!

जिंतूर (एम एजाज जिंतुरकर) २९ एप्रिल २०२५ की औरंगाबाद के संशोधक अब्दुल अन्सार अब्दुल सत्तार ने स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड की ओर से इंटरडिसिप्लीनरी स्टडीज शाखा अंतर्गत शारीरिक शिक्षण इस विषय मे पीएचडी पदवी प्रदान की गई! उनके संशोधन मे मराठवाडा के विवाहित महिला शिक्षिका वो के मानसिक और शारीरिक आरोग्य पर ताणतणाव का परिणाम की स्टडी की दि २८ एप्रिल को आयोजित ऑनलाईन व्हायवा व्होसे मे अब्दुल अन्सार ने सादरीकरण कर संशोधन का निष्कर्ष रखा! ५७ से अधिक सहभागी उपस्थित थे! व्हायवा समिती के

अध्यक्ष डॉ चंद्रकांत बाविस्कर थे! बाह्य परिक्षक डॉ मनोहर माने, और मार्गदर्शक प्रा डॉ सिंकु कुमार सिंग,की उपस्थित थे! उपस्थित सदस्यो ने प्रश्न किये! और अन्सार ने सभी प्रश्नो के समाधानकारक उत्तर दिये! उनकी उत्कृष्ट कामगिरी के आधार पर पीएचडी पदवी के लिये! शिफारस की गई! ये संशोधन स्कूल ऑफ एज्युकेशनल सायन्स,एस आर टी एम यु, नांदेड के डॉ सिंकु कुमार सिंग के मार्गदर्शन मे पूरा किया! अब्दुल अन्सार का ये संशोधन शिक्षीका वो के मानसिक आरोग्य पर समाज मे जागरूकता निर्माण करणे और धोरणकृतावो के लिये! मार्गदर्शक साबीत हो गी!

बीड: तालुकास्तरीय शांति समिति की बैठक में बंद पड़ी चौकियों को पुनः शुरू करने की मांग

बीड, प्रतिनिधि:

बीड शहर पुलिस स्टेशन में आज पुलिस अधीक्षक श्री कावत साहब की अध्यक्षता में तालुकास्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शहर के सामाजिक प्रतिनिधियों एवं समिति सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए।

शांति समिति के सदस्य मुसा खान पठान ने बैठक में बोलते हुए बीड शहर की बंद पड़ी पुलिस चौकियों को दोबारा शुरू करने की मांग उठाई। उन्होंने विशेष रूप से कोतवाली वेस जुना बाजार चौकी, माळी वेस पुलिस चौकी, और किला मैदान क्षेत्र में स्थित पुलिस चौकी, जो वर्तमान में निष्क्रिय हैं, उन्हें पुनः कार्यरत किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

साथ ही उन्होंने कहा कि शहर के दो प्रमुख महाविद्यालय – मिलिया कॉलेज और बलभीम कॉलेज में विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु इन स्थानों पर पुलिस की सतत उपस्थिति आवश्यक है। इसके लिए संबंधित चौकियों को जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए।

पुलिस अधीक्षक ने समिति के सुझावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

तस्वीर नामा

योद्धा।

गूजरा है साहस का ऐसा दिवाना।
हक लिए अपनों से भी टकराना।
कमज़ोरों का बनाया था ,संघ ।
यारो कुर्बानी को ये भुल न जाना।

– काजी मखदूम
९२७०५७४४४४

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

जाति जनगणना पारदर्शी, समावेशी और राजनीतिक दखल से मुक्त होनी चाहिए: प्रोफेसर सलीम इंजीनियर

नई दिल्ली, ०१ मई २०२५: जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया है।

मीडिया को जारी एक बयान में जमाअत उपाध्यक्ष ने कहा, हम आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत करते हैं। जाति अभी भी भारत में एक मजबूत सामाजिक संरचना है जो शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक पहुंच को आकार देती है। यह पिछड़ी जातियों, दलितों और आदिवासियों द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए एक सामाजिक, कानूनी, प्रशासनिक और नैतिक आवश्यकता है।यह सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की निगरानी के लिए सटीक डेटा प्रदान करेगा और इन समुदायों को सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित करने में मदद करेगा। यह सर्वविदित तथ्य है कि केवल मापी गई चीज का ही प्रबंधन किया जा सकता है, और इसलिए सूचित नीति निर्माण और समावेशी विकास के लिए जातिगत डेटा आवश्यक है। जाति जनगणना इन उपेक्षित समुदायों के लिए सकारात्मक व्यवहारिक नीतियों की निगरानी और उन्हें मजबूत करने के लिए सटीक आंकड़े उपलब्ध कराएगी, विशेष रूप से बढ़ते निजी क्षेत्र और घटती सरकारी नौकरियों के संदर्भ में।

सरकार के निर्णय को स्वीकार करते हुए प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने जाति जनगणना कराने में सरकार की पूर्व अनिच्छा पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, जैसा कि संसद में दिए गए आधिकारिक बयानों से पता चलता है, सरकार अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) से परे जाति जनगणना के पूरी तरह से खिलाफ थी। लेकिन ऐसा लगता है कि उसने अंततः इसकी प्रभावशीलता को स्वीकार कर लिया है। खराब मंसूबा और क्रियान्वयन के कारण २०११ की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना की विफलता एक मजबूत ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित करती है। हालांकि, हमारा मानना है कि हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने और अनुच्छेद १४, १५ और १६ के तहत संवैधानिक गारंटी को बरकरार रखने के लिए यह प्रक्रिया पारदर्शी, समावेशी और राजनीतिक दखल से मुक्त होनी चाहिए।

जमाअत उपाध्यक्ष ने आगे कहा, सरकार द्वारा पूरी प्रक्रिया के लिए एक निश्चित समयसीमा जारी की जानी चाहिए। जाति जनगणना के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया जाना चाहिए। जाति जनगणना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय होना चाहिए न कि राजनीतिक लाभ। टेक्नोलॉजी का उपयोग, जैसे कि प्री-लोडेड जाति विकल्पों के साथ इंटरनेट-सक्षम डिवाइस, सटीकता और दक्षता सुनिश्चित करेगा। हम उन लोगों से सहमत नहीं हैं जो जाति जनगणना का विरोध करते हैं और दावा करते हैं कि यह विभाजन को मजबूत करती है या प्रशासनिक रूप से जटिल है। भारत की जनगणना में पहले से ही धर्म और भाषा की गणना होती है, तथा १९५५ से एससी/एसटी की गणना होती आ रही है। इनसे संघर्ष को बढ़ावा नहीं मिला है। गणना संभव है, जैसा कि बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों ने सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है।हम सभी हितधारकों से इस परिवर्तनकारी अभ्यास का समर्थन करने का आह्वान करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी और हाशिए पर पड़े लोगों को न्याय मिलेगा।

राजधानी दिल्ली में उत्साहपूर्वक मनाया गया महाराष्ट्र दिवस

ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और हापूस आम प्रदर्शनी ने बढ़ाया समारोह का आकर्षण

नई दिल्ली, ०१ मई:

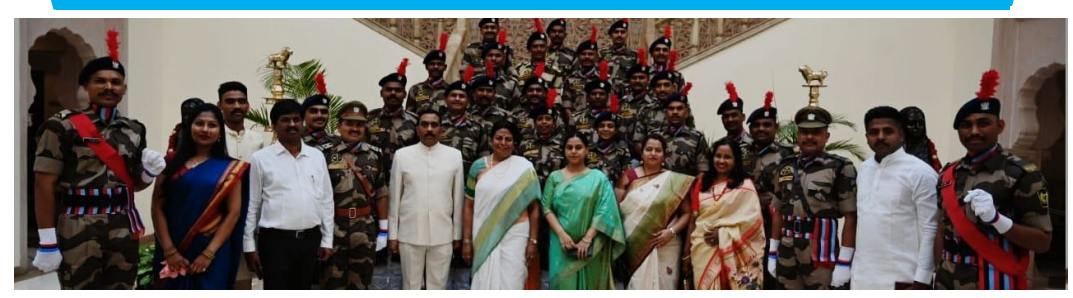

महाराष्ट्र राज्य की ६६वीं वर्षगांठ के अवसर पर राजधानी दिल्ली में महाराष्ट्र दिवस पूरे उत्साह और पारंपरिक गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र सदन, कस्तूरबा गांधी मार्ग और कॉपर्निकस मार्ग पर निवासी आयुक्त एवं सचिव आर. विमला के हाथों ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के बाद उपस्थित अधिकारियों और अतिथियों ने राष्ट्रगान और राज्यगीत 'गर्जा महाराष्ट्र माझा' गाकर ध्वज को सलामी दी।

इस अवसर पर अपर निवासी आयुक्त डॉ. नीवा जैन, सहायक निवासी आयुक्त डॉ. राजेश अडपावार, श्रीमती स्मिता शेलार, महाराष्ट्र परिचय केंद्र की उपसंचालक अमरजीत कौर अरोड़ा, सूचना अधिकारी अंजु निमसरकर सहित महाराष्ट्र सदन के कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी, दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों के अधिकारी व कर्मी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

महाराष्ट्र दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम

दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से शाम को महाराष्ट्र और गुजरात स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तथा केंद्रीय गृहमंत्री एवं सहकार मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

इस मौके पर दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत मराठी भाषी विशिष्ट व्यक्तियों से संवाद किया जाएगा और उन्हें महाराष्ट्र दिवस की शुभकामनाएं दी जाएंगी। साथ ही महाराष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन भी किया जाएगा। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक गौरव का प्रदर्शन

कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित महाराष्ट्र सदन में महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने वाला विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। हापूस आम प्रदर्शनी का उद्घाटन महाराष्ट्र सरकार के कृषि विभाग के सहयोग से और कोकण हापूस आंबा उत्पादक संघ, देवगढ़-सिंधुदुर्ग के संयुक्त तत्वावधान में १ और २ मई को ऋख टैग प्राप्त हापूस आम की बिक्री प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन निवासी आयुक्त आर. विमला के हाथों हुआ।

इस अवसर पर 'महाराष्ट्र का सुगंधित राजा' कहे जाने वाले हापूस आम की खरीददारी का सुनहरा अवसर दिल्लीवासियों को मिला है। आयोजकों ने दिल्ली के मराठी और अमराठी नागरिकों से आह्वान किया है कि वे महाराष्ट्र दिवस पर आयोजित इन विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अधिक संख्या में सहभागी बनें, जिससे महाराष्ट्र की गौरवशाली परंपरा और सांस्कृतिक वैभव जन-जन तक पहुंच सके।

'सनातनी एकता मंच' के नेताओं ने लगाया था रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तानी झंडा, दंगा फैलाने की साज़िश रचने वाले दो आतंकी गिरफ्तार

कोलकाता, १ मई:- पश्चिम बंगाल के एक रेलवे स्टेशन पर बने बाथरूम में पाकिस्तानी झंडा देखे जाने के बाद काफी सियासी बवाल मचा था. लेकिन अब पुलिस ने दावा किया है कि असल में ये राज्य में सांप्रदायिक तनाव और नफरत फैलाने का एक प्रयास था. इस सिलसिले में बनगांव जिले से पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने सांप्रदायिक अशांति भड़काने के आरोप में ये कार्रवाई की है. याद रहे कि इससे पहले दंगे भड़काने की साज़िश में पकड़े है दहशतगर्दों को बंगाली भाषा नही आती है और वे सिर्फ हिंदी बोल पाए है। आरोप है कि उन्हें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से दनागे भड़काने बंगाल भेजा गया ताकि ममता बनर्जी को बदनाम कर सके।

पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों ने स्टेशन के बाथरूम की एक दीवार पर पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज चिपकाया था. यही नहीं, दोनों ने योजना बनाई थी कि वो दीवार पर 'हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद' भी लिखेंगे. पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी एक स्थानीय धार्मिक संगठन 'सनातनी एकता मंच' के सदस्य हैं. इनके नाम चंदन मलाकर और प्रोज्ञजीत मोंडल बताए गए हैं.

सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की ये कोशिश गोपालनगर पुलिस थाना क्षेत्र में की गई. जहां ३० अप्रैल की रात अकईपुर रेलवे स्टेशन के पास एक शौचालय की दीवार पर पाकिस्तानी राष्ट्रीय ध्वज चिपका हुआ पाया गया था. इसकी जानकारी पुलिस की दी गई. पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ऐसा जानबूझकर किया गया था.

द पर मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि चंदन और प्रोज्ञजीत स्थानीय निवासी हैं और एक राजनीतिक पार्टी और सनातनी एकता मंच के सक्रिय सदस्य हैं.

पुलिस ने कहा कि वो आरोपी सांप्रदायिक अशांति को भड़काने के लिए इस तरह की साजिश रचने वालों को सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय की परीक्षा समय-सारणी में जुजवी बदलाव

२, ३ और ६ मई की परीक्षाएं आगे बढ़ाई गईं, परीक्षार्थी ध्यान दें-प्रो.अमर शेख

(प्रतिनिधि)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय द्वारा घोषित की गई स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम तथा द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं की समय-सारणी में आंशिक बदलाव किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, २ और ३ मई २०२५ को विश्वविद्यालयीय परीक्षाएं निर्धारित थीं, लेकिन इन्हीं तारीखों पर राज्य स्तर की च-क डङइ ३ धशरीं उएढ - २०२५ परीक्षा और ६ मई २०२५ को राष्ट्रीय स्तर की चार्टर्ड अकाउंटेंट (उ-) अंतिम वर्ष परीक्षा आयोजित की जा रही हैं।

इन दोनों ही व्यावसायिक परीक्षाओं में विश्वविद्यालय तथा इससे संबद्ध महाविद्यालयों के कई छात्र सम्मिलित हो रहे हैं। चूंकि उपरोक्त तिथियों पर एक ही दिन दो-दो परीक्षाएं पड़ रही थीं, इससे छात्रों का शैक्षणिक नुकसान होने की संभावना थी। इसे ध्यान में रखते हुए, सिनेट सदस्य डॉ. नरेंद्र काळे और प्रा. बंडू सोमवंशी ने विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुरोध किया था कि संबंधित तिथियों की परीक्षाएं आगे बढ़ाई जाएं।

विश्वविद्यालय ने इस मांग पर तत्परता से संज्ञान लेते हुए ३० अप्रैल २०२५ को एक पत्र जारी कर सूचित किया है कि २, ३ और ६ मई २०२५ को होने वाली स्नातक अंतिम वर्ष वाणिज्य संकाय और स्नातकोत्तर प्रथम तथा द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। इन स्थगित परीक्षाओं को संबंधित पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा तिथि के बाद आयोजित किया जाएगा। नई तिथियों की जानकारी शीघ्र ही अलग से घोषित की जाएगी।

इस संदर्भ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी - शरदचंद्र पवार पदवीधर संघटना के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रो. अमर शेख ने सभी परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे इस संशोधित कार्यक्रम की जानकारी अवश्य नोट कर लें।

जंग हुई तो चीन दिखा सकता है पाक को पीठ

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले को लेकर रविवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तानी उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक़ डार के बीच फ़ोन पर हुई बातचीत के बाद मीडिया में दावा किया जाने लगा कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ये दावा सिर्फ इस आधार पर हो रहा है कि चीन ने पाकिस्तान की 'निष्पक्ष जांच' वाली मांग का समर्थन किया है।

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंग्रेज़ी दैनिक ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, चीन उम्मीद करता है कि दोनों पक्ष (भारत और पाकिस्तान) इस मामले में संयम बरतेंगे। अब अहम सवाल यह है कि अगर जंग हुई तो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा

? अगर बात कारगिल जंग (१९९९) की करें तो तब चीन ने पाकिस्तान का खुलकर या प्रत्यक्ष रूप से सैन्य या राजनयिक समर्थन नहीं किया था। भले ही चीन और पाकिस्तान के बीच गहरे रणनीतिक संबंध हैं, जिन्हें अक्सर सदाबहार दोस्ती कहा जाता है। पाकिस्तान तो चीन के साथ अपने संबंधों को लेकर बड़े-बड़े दावे करता है। पाकिस्तान के नेता हर संकट के वक्त बीजिंग पहुंच जाते है कटोरा लेकर। दरअसल कारगिल संघर्ष के दौरान चीन की प्रतिक्रिया काफी सधी हुई थी। चीन ने तब भी आधिकारिक तौर पर भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने और बातचीत से जटिल मामलों को हल करने का आग्रह किया था। यानी चीन उस समय पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ था।

चीन ने नियंत्रण रेखा का सम्मान करने का दोनों पक्षों से आग्रह किया था। यह परोक्ष रूप से पाकिस्तान की आलोचना थी, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करके भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के चीनी विभाग के अध्यक्ष प्रो. तान चुंग कहते थे कि चीन बहुत प्रेक्टिल देश है। वह बहुत सोच-समझकर ही खुलकर किसी देश के साथ खड़ा होता है।

रोखठोक

विवेक शुक्ला

दिल्ली

जानकारों का कहना है कि जब कारगिल युद्ध के समय तत्कालीन पाकिस्तानी सेना प्रमुख परवेज़ मुशर्रफ़ समर्थन मांगने चीन गए, तो चीनी नेतृत्व ने उन्हें पीछे हटने और मामले को शांतिपूर्वक सुलझाने की सलाह दी। चीन इस संघर्ष को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता था। चीन का मत था कि दो परमाणु-सशस्त्र पड़ोसियों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहने चाहिए।

दरअसल तब चीन ने पाकिस्तान की कार्रवाई की सार्वजनिक रूप से निंदा नहीं की थी, पर उसने पाकिस्तान की कारगिल में सैन्य घुसपैठ का समर्थन भी नहीं किया था। उसने बातचीत के जरिए तनाव कम करने पर जोर दिया था। इसलिए, यह कहना गलत होगा कि चीन ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया था।

हाँ, १९६५ और १९७१ के भारत-पाक युद्धों में चीन ने पाकिस्तान का कह सकते हैं समर्थन किया था, लेकिन खुलकर साथ होने की व्याख्या थोड़ी जटिल है और दोनों युद्धों में उसकी भूमिका थोड़ी अलग थी। चीन ने १९६५ की जंग के वक्त भारत की कड़ी आलोचना की और पाकिस्तान को अपना पूर्ण राजनयिक समर्थन दिया। चीन ने भारत पर सिक्किम सीमा पर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सैन्य कार्रवाई की धमकी दी। उसने सीमा के पास अपनी सेना की कुछ गतिविधियाँ भी बढ़ाईं, जिससे भारत पर दूसरा मोर्चा खुलने का दबाव बना। यह पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण नैतिक और रणनीतिक समर्थन था। हालांकि चीन ने धमकियाँ दीं और दबाव बनाया, लेकिन उसने भारत के खिलाफ सीधे तौर पर कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई नहीं की। उसका समर्थन मुख्यतः राजनयिक और मनोवैज्ञानिक दबाव तक ही सीमित रहा। तो कह सकते हैं कि चीन १९६५ में खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में था, उसने राजनयिक समर्थन दिया और सैन्य दबाव भी बनाया, लेकिन वह सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुआ।

चीन ने १९७१ में भी पाकिस्तान का राजनयिक समर्थन जारी रखा। हालांकि १९७१ में चीन का दबाव काफी कम था। कूटनीति मामलों के जानकार इसका एक अहम कारण बताते हैं- भारत-सोवियत संधि (१९७१)। इस संधि ने चीन को हतोत्साहित किया, क्योंकि भारत पर हमले की स्थिति में सोवियत संघ के हस्तक्षेप की संभावना थी। चीन उस समय सोवियत संघ के साथ तनावपूर्ण संबंध रखता था। इसके साथ ही सर्दियों में हिमालय के दुर्गम दर्रों से बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई करना चीन के लिए बहुत मुश्किल था। मतलब चीन ने १९७१ में भी कोई सीधा सैन्य हस्तक्षेप नहीं किया।

एक बात समझ लें कि भले ही भारत-चीन के बीच सीमा विवाद है, पर चीन को मालूम है कि भारत उसके उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार है। यह बात उसे आजकल खासतौर पर समझ आ रही होगी क्योंकि अमेरिका उस पर भारी-भरकम टैरिफ लगा रहा है। फिलहाल भारत-चीन के बीच सालाना

आपसी व्यापार १२५ बिलियन ड़ॉलर तक पहुंच गया है। भारत-चीन ने एक तरह से मान लिया है इनके जटिल सीमा विवाद का कोई हल निकले या ना निकले,पर ये अपने आपसी कारोबारी संबंधों को प्रभावित नहीं होने देंगे। याद करें कि लद्दाख सीमा पर चीन की ओर से हिंसक झड़प करने और अतिक्रमण के बाद अखिल भारतीय स्तर पर चीनी सामान के बहिष्कार की मांग ने जोर पकड़ा था।

भारत चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों तथा मोबाइल फोन कंपोनेंट्स का बहुत बड़े स्तर पर आयात करता है। हमारी फार्मा कंपनियों की चीन पर निर्भरता तो खासी अधिक है। हमारी फार्मा कंपनियां अपनी जेनेरिक दवाओं को बनाने के लिए क़रीब ८५ फ़ीसदी एक्टिव फ़ार्मास्यूटिकल इनग्रेडिएंट्स (एपीआई) चीन से आयात करती है। एपीआई यानी दवाओं को बनाने के काम में आने वाला कच्चा माल। भारत में एपीआई का उत्पादन बेहद कम है और जो एपीआई भारत में बनाया जाता है उसके फ़ाइनल प्रोड्क्ट बनने के लिए भी कुछ चीज़ें चीन से लेनी पड़ती है।

भारत-चीन के बीच आपसी व्यापार तो कुलांचे भर रहा है, पर इससे भारत को फायदा नहीं हो रहा है। नुकसान इस लिहाज से होता है कि हम उससे जितना माल खरीदते हैं, उस तुलना में बेहद कम उसे बेचते हैं। हमारा चीन के साथ कुछ साल पहले तक व्यापार घाटा २९ अरब रुपए तक का हो गया था। पूर्व विदेश सचिव श्री हर्षवर्धन श्रृंगला भी मानते हैं कि इस व्यापार घाटे को संतुलित करने की जरूरत है। पर फिलहाल सबकी निगाहें इस बात पर है कि भारत-पाक के बीच जंग वाली स्थिति बनी तो चीन किसका साथ देगा। तो जान लें कि चीन युद्ध की स्थिति में पाक का खुलकर साथ नहीं देगा।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com